

# भारतीय जनता पार्टी

श्री लालकृष्ण आडवाणी  
लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता  
भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा क्रान्ति रैली में  
दिया गया भाषण

नई दिल्ली-9 अगस्त, 2008

श्री राजनाथ सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमित ठक्कर, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, बहनो और भाइयो,

आप सबको हार्दिक अभिवादन।

कल से बीजिंग में ओलम्पिक खेल शुरू हुए हैं। मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भेजता हूँ।

\*\*\*

आज 9 अगस्त है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ है।

यह पावन दिन है।

यह क्रान्ति के उद्घोष का दिन है।

सन् 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी ने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का नारा दिया था। उस दिन से जो आंदोलन शुरू हुआ वह 'भारत छोड़ो आन्दोलन' या quit india movement के नाम से चिरस्मरणीय रहा। इस आन्दोलन की परिणति पांच साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी में हुई।

अब छह दिन बाद 15 अगस्त का पावन दिन आएगा जब भारत अपनी आजादी की 61वीं सालगिरह मनाएगा।

लेकिन हमें सदैव याद रखना चाहिए कि 9 अगस्त के बिना 15 अगस्त संभव नहीं था।

हम जानते हैं कि "भारत छोड़ो आन्दोलन" का श्रीगणेश करते हुए महात्मा गांधी ने एक और घण्टावाक्य भारत की जनता को दिया था— करो या मरो। do or die।

यानि संघर्ष, त्याग और बलिदान के बिना स्वतंत्रता पाना संभव नहीं।

आज 9 अगस्त को जब हजारों युवा एक क्रान्ति रैली के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है कि फिर एक बार संघर्ष का रास्ता अपनाने का समय आ चुका है।

- संघर्ष भारत की एकता और अखंडता के लिए।
- संघर्ष भारत की सुरक्षा के लिए,  
विशेषकर आंतरिक सुरक्षा के लिए।  
आतंकवाद से देश को बचाने के लिए।
- संघर्ष आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा के लिए,

उसे मंहगाई से बचाने के लिए।

- संघर्ष युवाओं के रोजगार के लिए,  
उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए।
- संघर्ष गांव, किसान और खेती की रक्षा के लिए।
- संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए,  
संसद को 'खरीद-फरोख्त की मंडी' बनाकर अपनी सत्ता बचाने वालों से  
देश को बचाने के लिए।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि संघर्ष जरूरी बन गया है कि हिन्दू-विरोधी मानसिकता से देश की राजनीति को बचाने के लिए।

हमारा देश विशाल और विविधता से भरा हुआ है। भारत की संस्कृति रही है कि यहां सभी वर्गों का सम्मान होता है, चाहे वह वर्ग छोटा हो या बड़ा।

परन्तु आजकल वोटबैंक की राजनीति के चलते एक विकृत मानसिकता देश में पनप रही है। गैर-उत्तर भारतीय मानसिकता से महाराष्ट्र में कुछ लोगों को लगता है कि राजनीतिक लाभ होगा।

इसी तरह की संकीर्ण राजनीति के साथ-साथ जातिवाद की राजनीति भी चलाई जा रही है। यह राष्ट्र-हित में नहीं है।

अब कांग्रेस और अन्य कुछ दलों को लगने लगा है कि हिन्दू-विरोधी मानसिकता से उन्हें राजनीतिक लाभ होगा।

कश्मीर की घटनाओं के पीछे यही हिन्दू-विरोधी मानसिकता थी।

कांग्रेस और उनके कुछ मित्र दलों ने इसी प्रकार की हिन्दू विरोधी मानसिकता को रामसेतु मुद्दे पर भी दिखाया है।

\*\*\*

कई दिनों से जम्मू सुलग रहा है और देश के अन्य भागों में सभी हिन्दू क्रोधित हैं। क्यों? अमरनाथ एक तीर्थस्थान है। यह कश्मीर में है। देश के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यात्रा के लिए अमरनाथ जाते हैं।

यह बहुत कठिन यात्रा है।

आप जैसे युवाओं को कोई कठिनाई नहीं होती।

परन्तु माताओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराना आवश्यक लगा।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड सरकार द्वारा गठित है। गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं।

सरकार ने निर्णय लिया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 100 एकड़ जमीन दी जाए।

सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी।

कांग्रेस- पी.डी.पी. की गठबन्धन सरकार थी। उस सरकार ने निर्णय लिया था।

निर्णय सही था। उसका स्वागत हुआ।

लेकिन अचानक कश्मीर घाटी में विदेशी और भारत विरोधी ताकतों की साजिश से उपद्रव शुरू हुआ।

कहा गया कि जमीन देने का फैसला वापिस लो।

कहा गया कि इससे कश्मीर का demographic profile बदल जाएगा।

साल में दो महीनों के लिए अस्थायी ढांचा (temporary structures) बनाकर यात्रियों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने से—और वह भी केवल 100 एकड़ जमीन पर—कश्मीर के अस्तित्व और पहचान के लिए खतरा कैसे बन सकता है? और कश्मीर की पहचान क्या है? क्या यह भारत का अभिन्न अंग नहीं है?

यह सब हास्यास्पद था।

लेकिन वहां की कांग्रेस—नीत सरकार भारत विरोधी ताकतों के सामने झुक गई।

केन्द्र की कांग्रेस—नीत सरकार ने झुकने के लिए कहा।

कांग्रेस के रवैये से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

पहली, वह राष्ट्र—विरोधी ताकतों के दबाव में आसानी से झुक सकती है।

दूसरी, कांग्रेस की नजर में हिन्दुओं के लिए, हिन्दुओं की न्यायपूर्ण मांग के लिए कोई स्थान नहीं।

इसलिए आज जम्मू ज्वालामुखी बन गया है। मैं जम्मू की स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 'करो या मरो' को घोषवाक्य बनाकर संघर्ष का रास्ता अपनाया है।

अन्याय को सहना कायरता का लक्षण है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संघर्ष केवल जम्मूवासियों का ही नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतवासियों का संघर्ष है। जम्मू के लोग हाथ में तिरंगा लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

यह 100 एकड़ भूमि का प्रश्न नहीं है।

यह हमारी मातृभूमि की पहचान का प्रश्न है।

यह संघर्ष दोहरे मापदंड के खिलाफ संघर्ष है।

अलगाववादी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष है।

लगभग 60 साल पहले डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष चलाया था।

'एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।' यह उस समय का नारा था।

आज फिर एक बार कहने का वक्त आ गया है कि 'एक देश में दो मापदंड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।'

भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चलने नहीं देगी।

हम इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रियों के लिए जमीन का मुद्दा हिन्दू—मुसलमान मुद्दा नहीं है।

जहां मुसलमान या ईसाई तीर्थस्थान हैं, वहां यात्रियों की सुविधा के लिए जमीन की आवश्यकता है तो उन्हें मिलनी चाहिए और दी भी गई है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर हज यात्रियों के लिए विशेष टर्मिनल हैं।

यदि हमारी सरकार बनी तो हम भारत के सभी तीर्थस्थलों पर सुविधा और सुरक्षा के प्रबन्ध को सुधारने के लिए वृहद् योजना शुरू करेंगे।

इसमें यात्रियों की सुरक्षा का भी प्रश्न है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक तीर्थस्थल पर हडकंप मचा और इस त्रासदी में 145 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई।

ऐसा नहीं होना चाहिए था।

\*\*\*

भारत ने मजहब के मामलों में कभी भी भेदभाव नहीं किया है, न आगे कभी करेगा।

इसलिए मैं कश्मीर सहित भारत के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि वे भी अमरनाथ के मसले पर हिन्दुओं की मांग का समर्थन करें।

## यू.पी.ए. सरकार—देश के लिए खतरा

आतंकवादियों को कोई डर नहीं।

क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।

कार्रवाई करने की इच्छा—शक्ति नहीं।

मेरे एक सहयोगी श्री किरीट सोमैया ने 'सूचना का अधिकार' (RTI) में Application डालकर यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में हुए सभी महत्वपूर्ण आतंकवादी हमलों की जानकारी ली।

सरकार स्वयं यह कह रही है कि वर्ष 2005 से 2008 तक 23 आतंकवादी हमले हुए। कुल 541 लोग मौत के शिकार हुए।

लेकिन अभी तक एक भी आतंकवादी मामले में अदालती कार्यवाही पूरी नहीं हुई है और एक भी दोषी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है।

यह सरकार कितनी नकारा है इसका अंदाजा इससे लगता है कि हाल ही में एक ट्रिब्यूनल ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन simi के ऊपर लगाए गये प्रतिबंध को यह कहकर उठा लिया कि उसे राष्ट्र—विरोधी घोषित करने के लिए सरकार ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं।

जब देशभर में इस निर्णय के खिलाफ आक्रोश का स्वर मुखर हुआ तो अगले ही दिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में stay के लिए आवेदन किया।

लेकिन इसी बीच केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने simi पर से प्रतिबंध हटाने के निर्णय का स्वागत भी किया।

देशवासी प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने इन दो मंत्रियों को बुलाकर उनसे पूछा कि क्यों आपने मंत्रिमंडल के collective responsibility principle का उल्लंघन किया?

## सरकार संसद के सत्र को क्यों नहीं बुला रही है?

इसलिए कि वह सदन के सामने आने से डर रही है।

संसद को लांछित करके, सांसदों की खरीद—फरोख्त करके वह सदन में किस मुंह से आ सकती है?

लेकिन संसद का सत्र न बुलाना संसद का अपमान है, लोकतंत्र की अवहेलना है।

मेरी मांग है कि सरकार संसद का मानसून सत्र तुरन्त बुलाए और विरोधी दलों के सवालियों के जवाब दे।

\*\*\*